

सं.ओ.वि.०/एफ.डी.०/161-85/52142.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं गैडोर टूल्ज इण्डिया प्रा. लि.०, इण्डस्ट्रीयल, ऐरिया 10/12, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वर्षतलाल भा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री वसंत लाल शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि.०/एफ.डी.०/231-४५/52148.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं एन.सी.० इण्डस्ट्रीज ५-सी-२३, एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री योगेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला हैं या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है;

क्या श्री योगेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि.०/एफ.डी.०/158-४५/52154.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं राना टैक्सटाईल विर्किंग मिल सेवटर-६, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुखी राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त तथा उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है;

क्या श्री सुखी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि.०/एफ.डी.०/254-४५/52160.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं लैंडस वर्ग इण्डिया प्रा. लि.०, ५९-ए, एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जगदीप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है;

क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?